कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, यूरोपीय संघ ने व्यवसायों के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) को लागू करते हुए भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

01 कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए, यूरोपीय संघ (EU) एक प्रयोग शुरू कर रहा है जो आयातों के लिए जलवायु परिवर्तन नीतियों का विस्तार करेगा।

02 इस नीति को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) अर्थात **कार्बन सीमा कर** एक ऐसा कर है, जो आयातकों और गैर-यूरोपीय संघ के निर्माताओं को यूरोपीय संघ की सीमाओं के भीतर बेचे जाने वाले वस्तुओं से जुड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान किया जाता है।

03 आयातकों को निर्दिष्ट वस्तुओं के माध्यम से यूरोपीय संघ में लाए गए CO_2 के प्रति मीट्रिक टन के लिए कार्बन आयात प्रमाण पत्र/परमिट खरीदने की आवश्यकता होगी।

04 प्रमाण पत्र की कीमत आयात किए जा रहे माल की कार्बन तीव्रता और प्रति मीट्रिक टन कार्बन मूल्य पर निर्भर हो सकती है जो यूरोपीय संघ के उत्पादकों द्वारा भुगतान की जा रही घरेलू कार्बन कीमत के समान होगी।

कार्बन टैक्स क्या है ?

कार्बन टैक्स, सरकार द्वारा निर्धारित एक कीमत है जिसके तहत उत्सर्जकों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए भुगतान करना होता है। जिससे व्यवसायकर्त्ताऔर उपभोक्ता कर का भुगतान करने से बचने हेतु अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन बदलने या नई तकनीकों को अपनाने जैसे कदम उठाएंगे।

कार्बन सीमा कर क्या है ?

कार्बन सीमा समायोजन कर, उत्पादन के परिणामस्वरूप उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की संख्या आधारित एक आयात शुल्क है। जो कार्बन की कीमत के रूप में, कार्बन उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में, यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है।

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) क्या है ?

यह व्यापार नीति उपकरणों का एक उभरता हुआ समूह है, जिसका उद्देश्य कार्बन-गहन आर्थिक गतिविधि को अपेक्षाकृत कठोर जलवायु नीतियों वाले अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाने और अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु नीतियों वाले क्षेत्रों में जाने से रोकना है।

भारत की चिंता

भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि यूरोपीय संघ में निर्यात होने वाले भारतीय वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती हैं, जिससे वे खरीदारों के लिए कम आकर्षक हो सकते हैं और मांग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह के कर उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाली कंपनियों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

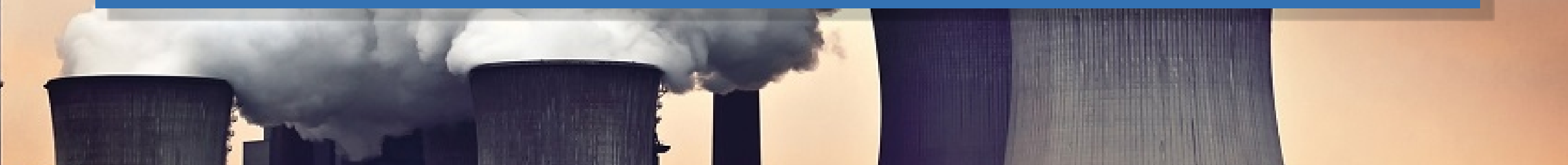

लागू होने के कारण

- **कार्बन कर** जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करके कम प्रदूषण वाले ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (Co_2) जैसे प्रमुख ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित किया जा सकता है।
- सरकारें कार्बन टैक्स लगाकर महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित कर सकती हैं। एकत्रित राजस्व का उपयोग ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है।
- **कार्बन कर राजस्व,** संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादक को भी प्रत्साहन राशि दे सकता है, जैसे कि **भूख, गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट को कम करना।**

कार्बन टैक्स

गुण

01 प्रदूषकों को कार्बन उत्सर्जन की बाहरी लागत का भुगतान करना पड़ता है।

02 सैद्धांतिक रूप में, अधिक सामाजिक दक्षता को सक्षम बनाता है, क्योंकि हम पूर्ण सामाजिक लागत का भुगतान करते हैं।

03 राजस्व में वृद्धि करता है जिसका उपयोग प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए किया जा सकता है।

04 व्यवसायों और उपभोक्ताओं के विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उदाहरण के लिए, **सौर ऊर्जा**।

05 अत्यधिक कार्बन प्रदूषण से जुड़ी पर्यावरणीय लागत को कम करता है।

दोष

01 व्यापारियों के अनुसार यह उच्च कर निवेश और आर्थिक विकास को हतोत्साहित कर सकता है।

02 कर चोरी करने वाली कंपनियों द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा, जो गुप्त रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं।

03 बाहरी लागतों को मापना मुश्किल हो सकता है। यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि वास्तव में उच्च कर कितना होना चाहिए।

04 प्रदूषण को मापने और कर एकत्र करने में प्राशासनिक लागत।

05 कंपनियां कार्बन टैक्स के बिना देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर सकती हैं।

चुनौतियाँ

01 CBAM के कारण भारत के धातु उद्योग को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में भारत के लौहइस्पात से 8.2 बिलियन डॉलर और एल्यूमीनियम निर्यात का 27% यूरोपीय संघ को निर्यात किया गया था।

02 जैसा कि यूरोपीय संघ CBAM सूची में अधिक उत्पादों को शामिल करता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से निर्यात और उच्च लागत में अरबों डॉलर का नुकसान होता है।

03 CBAM के माध्यम से, उत्सर्जन को डीकार्बोनाइज करने और कम करने के सभी प्रयास सीधे 2026 तक CBAM वित्तीय दायित्व में कमी में बदल जाएंगे।

आगे की राह

भारत में कार्बन कर का स्पष्ट निर्धारण नहीं है। वह 2021 में 54.7% उत्सर्जन को कवर करता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी 2018 से अपरिवर्तित 2.5% को कवर करती है। किन्तु भारत सरकार, जब भी कार्बन टैक्स लगाने का फैसला करती है, जो सिर्फ कोयला और संशोधित स्वच्छ ऊर्जा कर पर कार्बन टैक्स तक सिमित है।

Follow Us: @khanglobalstudies

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Current Context

Recently, the European Union has expressed willingness to collaborate with India in easing the administrative burden for businesses while enforcing its Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Follow Us: @khanglobalstudies

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Key Points

01 To combat carbon leakage, the European Union (EU) is embarking on an experiment that would expand its climate change policies to imports.

02 The policy is called Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) or Carbon Border Tax which imposes importers and non-EU manufacturers to pay for the carbon emission linked to the goods they sell within the EU limits.

03 The importers will be required to purchase carbon import certificates/permits for each metric ton of CO_2 brought into the EU through specified goods.

04 The price of certificates could depend on carbon intensity of goods being imported and carbon price per metric ton which will be the same as domestic carbon price being paid by EU producers.

What is Carbon Tax?

Under a carbon tax, the government sets a price that emitters must pay for the greenhouse gas emissions they emit. Businesses and consumers will take steps, such as switching fuels or adopting new technologies, to reduce their emissions to avoid paying the tax.

What is Carbon Border Tax?

A carbon border adjustment tax is a duty on imports based on the number of carbon emissions resulting from the production of the product. As a price on carbon, it discourages emissions. As a trade-related measure, it affects production and exports.

What is a Carbon Border Adjustment Mechanism?

It is an emerging set of trade policy tools that aim to prevent carbon-intensive economic activity from moving out of jurisdictions with relatively stringent climate policies and into those with relatively less stringent policies.

India's Concern

India's concern is that these border taxes on its **goods entering the EU would increase the prices of Indian-made goods and make them less attractive to buyers and could negatively affect demand**. Such a tax could be a serious threat to companies with larger greenhouse gas footprints.

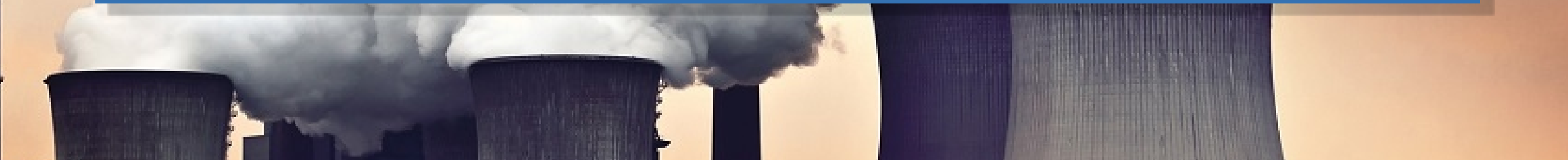

Reasons to Impose

- A carbon tax could **discourage the use of fossil fuels and encourage a shift to less-polluting fuels,** thereby limiting the carbon dioxide (CO_2) emissions that are by far the most prevalent greenhouse gas.
- Government **can raise significant revenue by imposing a carbon tax**; received revenue can be used to counteract economic harm caused by higher fuel prices.
- Carbon tax revenue **could also fund productive investments to help achieve the United Nations Sustainable Development Goals, including reducing hunger, poverty, inequality, and environmental degradation.**

Carbon Tax

Pros

01 Makes polluters pay external cost of carbon emissions.

02 In theory, enables greater social efficiency, as we pay full social cost.

03 Raises revenue which can be spent on mitigating effects of pollution.

04 Encourages firms and consumers to look for alternatives, e.g. solar power.

05 Reduces environmental costs associated with excess carbon pollution.

Cons

01 Business claim higher tax can discourage investment and economic growth.

02 May encourage tax evasion - firms polluting in secret to avoid tax.

03 It can be difficult to measure external costs - and how much tax should actually be.

04 Administration costs in measuring pollution and collecting tax.

05 Firms may shift production to countries without a carbon tax

Challenges

01

India's metal industry will face a significant challenge because of CBAM, given that **27% of India's iron, steel, and aluminium exports worth $8.2 billion in 2022 went to the EU.**

02

The impact is expected to rise as the EU adds more products to the CBAM list, **leading to potentially billions in lost exports and increased costs.**

03

Through CBAM, all efforts to decarbonise and abate emissions will **directly translate into a reduction of the CBAM financial obligation from 2026.**

Way Forward

India does not levy an explicit carbon price. Fuel excise taxes, an implicit form of carbon pricing, covered 54.7%, and fossil fuel subsidies covered 2.5% of emissions in 2021, unchanged since 2018. Whenever the Indian government decides to impose a carbon tax, it may consider removing the existing offset amount limited to coal and instead imposing a carbon tax in the form of a revised clean energy tax.

Follow Us: @khanglobalstudies